भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3576

दिनांक 22.03.2023 को उत्तर देने के लिए

सतत विकास लक्ष्य के संकेतक

3576. श्री ए. राजा:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्ष्य वर्ष 2030 तक सतत (एसडीजी) विकास लक्ष्यों को पूरा करने के संकेतकों के बारे में कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एसडीजी के सभी संकेतकों को प्राप्त कर लिया जाएगा और यदि नहीं, तो देश में वर्ष 2030 की समय-सीमा तक राज्य-वार किन-किन संकेतकों तक नहीं पहुंचा जा सका; और

(घ) महत्वपूर्ण संकेतकों, विशेषकर बुनियादी सेवाओं तक पहुंच, रक्ताल्पता, बाल मृत्यु दर, तम्बाकू के उपयोग आदि को कम करने के लिए लक्षित तिथि तक किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री (कारपोरेट कार्य मंत्रालय)

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा विकसित राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा के दिशानिर्देश के अनुसार केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श से उपयुक्त संकेतकों की पहचान की जाती है और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ मानचित्रित किया जाता है।

उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए ऐसे परिमाणात्मक संकेतकों को लिया जाता है जो निम्नांकित मापदंडों को पूरा करते हैं:

i. एसडीजी लक्ष्यों की प्रासंगिकता;
ii. राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा (एनआईएफ) द्वारा निर्देशित;
iii. आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणालियों से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डेटा की उपलब्धता;
iv. संबंधित मंत्रालयों/विभागों से सहमति;
v. मंत्रालयों द्वारा डेटा का स्वामित्व; और
vi. पर्याप्त डेटा कवरेज ताकि कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए डेटा उपलब्ध हो।

एसडीजी इंडिया सूचकांक, बेसलाइन रिपोर्ट 2018 में, 39 लक्ष्यों और 62 संकेतकों वाले 13 लक्ष्यों को लिया गया था। एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2019-20 में 54 लक्ष्यों और 100 संकेतकों वाले 16 लक्ष्यों को लिया गया था। एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 में 70 ध्येयों और 115 संकेतकों वाले 16 लक्ष्यों को लिया गया था।

(ग) और (घ): एसडीजी 17 लक्ष्यों और 169 संकेतकों का एक सेट है जिसका उद्देश्य 2030 तक किसी को पीछे न छोड़ते हुए मानव कल्याण की अधिकाधिक उपलब्धि के लिए विकास कार्यों को व्यवस्थित और कारगर बनाने में सहायता करना है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राज्य-वार उपलब्धि दर्शाने वाला एक विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है। भारत सरकार समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करती रही है और देश के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और मूलभूत सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। विभिन्न योजनाएं जैसेकि रोजगार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण और शहरी दोनो क्षेत्रों में आवासन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, कनेक्टिविटी रहित बस्तियों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई), घरों में शौचालय सुविधा प्रदान करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन, वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रौढ़ों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) लागू किया जा रहा है।

*****

अनुलग्नक

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	**समग्र स्कोर (100 में से)**
आंध्र प्रदेश	72
अरुणाचल प्रदेश	60
असम	57
बिहार	52
छत्तीसगढ़	61
गोवा	72
गुजरात	69
हरियाणा	67
हिमाचल प्रदेश	74
झारखंड	56
कर्नाटक	72
केरल	75
मध्य प्रदेश	62
महाराष्ट्र	70
मणिपुर	64
मेघालय	60
मिजोरम	68
नागालैंड	61
ओडिशा	61
पंजाब	68
राजस्थान	60
सिक्किम	71
तमिलनाडु	74
तेलंगाना	69
त्रिपुरा	65
उत्तर प्रदेश	60
उत्तराखंड	72
पश्चिम बंगाल	62
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	67
चंडीगढ़	79
दादरा और नगर हवेली	62
दमन और दीव	62
दिल्ली	68
जम्मू और कश्मीर	66
लद्दाख	66
लक्षद्वीप	68
पुदुच्चेरी	68
अखिल भारत	**66**

*****